tember, 1993. According to IPCL the main causes of the shortfall are:

(i) impact of the increase in the administered price of naphtha together with local levies; and

(ii) depressed product prices in international market and lower custom duties thereon resulting in pressure on the margins.

(iii) depressed prices due to sale of products imported duty free under value based advanced licensing system.

(iv) extended maintenance shut downs in Baroda and Nagothane complexes during April|May, 1993;

(c) No, Sir.

(d) and (e) The major reasons for the increased pressure on the margins of IPCL are higher domestic feedstock prices, higher financing charges, higher capital goods duty and high cost of power, fuel and utilities. The cost of naphtha delivered at IPCL's plant at Baroda is around 30 per cent higher than the international prices.

अनुभाग अधिकारी/आशुलिपिक के पद के लिए परीक्षा में हिन्दी के प्रयोग का विकल्प

313. **श्री कामेश्वर पासवान :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय सचिवालय के मंत्रालयों/विभागों में कार्यरत सहायकों/अनुभाग अधिकारियों तथा अन्य अधिकारियों को दैनंदिन कार्य में राजभाषा हिन्दी का प्रयोग करने के लिए बढ़ावा दिया जाता है;

(ख) क्या यह भी सच है कि सरकार ने विभागीय परीक्षा में प्रश्नों के उत्तर हिन्दी में दिये जाने के विकल्प संबंधी अनुदेश जारी किए हैं; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार अनुभाग अधिकारी/आशुलिपिक श्रेणी-ख की विभागीय परीक्षा में उम्मीदवारों को उत्तर हिन्दी में लिखने का विकल्प दिये जाने का विचार रखती है; यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्रीमती मारग्रेट आल्वा) : (क) जी, हां।

(ख) जी, हां।

(ग) अनुभाग अधिकारी/आशुलिपिक (ग्रेड "ख") की सीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षा के 5 प्रश्न-पत्रों में से 3 प्रश्न-पत्रों में हिन्दी में उत्तर दिए जाने का विकल्प पहले से ही उपलब्ध है।

FIRE INCIDENT AT NAMRUP PLANT OF HINDUSTAN FERTILIZER CORPORATION

*314. **SHRIMATI ILA PANDA :** Will the PRIME MINISTER be pleased to state :

(a) whether it is a fact that there was a case of fire in the ammonia unit at the Namrup plant of the Hindustan Fertilizer Corporation ;

(b) if so, what was the extent of loss in terms of life and property at the plant; and

(c) whether it is a fact that the fire was caused by extremists as reported in the press ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF CHEMICALS AND FERTILIZERS WITH ADDITIONAL CHARGE OF THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND MINISTER OF STATE IN THE DEPAREMENT OF ELECTRONICS AND DEPARTMENT OF OCEAN DEVELOPMENT (SHRI EDUARDO FALEIRO): (a) and (b) There was a fire in the cable trench of Namrup-II ammonia plant of Hindustan Fertilizer Corporation Limited (HFC) on 4th December, 1993. The fire was controlled within three hours. There was no loss of life or injury to any person. The estimated cost of replacement of the damaged items is about Rs. 175 lakhs.

(c) *Prima facie* there are no indications that the fire was caused by extremists.

REQUEST TO RESCIND NEWSPRINT CONTROL ORDER, 1992

@*315. SHRI V. NARAYANASAMY: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the President of Indian Newspaper Society recently urged Government to rescind the Newsprint Control Order, 1992 and allow the functioning of newspaper industry in a liberalised environment;

(b) if so, what steps have been taken by Government to rescind the Newsprint Control Order, 1992; and

(c) if the reply to part (b) above be in the negative, the reasons therefor ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INDUSTRY (DEPARTMENT OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT) AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INDUSTRY (DEPARTMENT OF HEAVY INDUSTRY) (SMT. KRISHNA SAHI) : (a) to (c) Yes, Sir. The Indian Newspaper Society have requested to rescind the Newsprint Control order, 1962. However, the request has financial implications for the domestic newsprint industry and is also dependant on the decisions in the Union Budget, 1994-95.

उत्तर प्रदेश स्थित विकास केन्द्र

316. **श्री ईश दत्त यादव** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार ने उत्तर प्रदेश स्थित विभिन्न औद्योगिक विकास केन्द्रों को क्या-क्या आधारभूत सुविधायें प्रदान की हैं;

(ख) विगत दो वर्षों के दौरान उत्तर प्रदेश के ऐसे केन्द्रों में निष्पादित किये गये कार्यों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह सच है कि उक्त विकास केन्द्र अपने-अपने क्षेत्रों में विकास कार्य को निष्पादित नहीं कर पा रहे हैं; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग) में राज्य मंत्री, उद्योग मंत्रालय (भारी उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) :

(क) से (घ) : विकास केन्द्र योजना, 1988 के अधीन केन्द्रों के विकास के लिए केन्द्र तथा राज्य सरकारों तथा वित्तीय संस्थाओं द्वारा धन दिया जाता है। सरकार ने उत्तर प्रदेश के विकास केन्द्रों के लिए अब तक 3.5 करोड़ रु. जारी किए हैं और 8 में से 6 परियोजनाओं को कार्यान्वयन के लिए अनुमोदित किया है जो राज्य सरकार द्वारा किया जाना है राज्य सरकार द्वारा भूमि का अधिग्रहण कर लिए जाने के बाद ही इस कार्य में तेजी आयेगी। योजना को 8वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कार्यान्वित किया जाना है। विकास केन्द्रों को बिजली, पानी, दूरसंचार, सड़क और बैंक जैसी मूल आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध करायी जायेंगी।

ग्रामीण क्षेत्रों में मुकदमों के शीघ्र निपटारे के लिए योजना

317. **श्री राम नरेश यादव** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार निकट भविष्य में ग्रामीण क्षेत्रों के मुकदमों के शीघ्र निपटारे के लिए कोई योजना तैयार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह सच है कि कुछ दिन पूर्व प्रधान मंत्री की अध्यक्षता में संपन्न मुख्य मंत्रियों और मुख्य न्यायाधीशों की गोष्ठी में [illegible]

@ Previously starred Question 255, transferred from 20th December, 1993.